अक्टूबर से किसानों को 170 रुपए क्विंटल का भाव मिलेगा

केंद्र ने गन्ना किसानों का मुंह मीठा किया

[ईटी ब्यूरो *नई दिल्ली*]

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने गन्ने के मिनिमम प्राइस में 17.25 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। चीनी मिलों को अब 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन से किसानों को गन्ना के लिए 170 रुपए प्रति क्विंटल देना होगा। इस सीजन के लिए यह राशि 145 रुपए प्रति क्विंटल है। इस फैसले से शुगर इंडस्ट्री के वर्किंग कैपिटल पर और प्रेशर बढ़ सकता है।

इंडस्ट्री पहले से ही कैश फ्लो के मामले में मुश्किलों का सामना कर रही है। हालांकि, इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से किसान खुश नहीं होंगे, क्योंकि इससे उनके बढ़े हुए खर्च की भरपाई नहीं होगी।

लेबर और डीजल की कीमत बढ़ने के चलते गन्ना किसानों की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब सबकी नजरें गन्ना के लिए राज्यों के एडवाइज्ड प्राइस पर होगी। एफआरपी के आधार पर अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु एडवाइज्ड प्राइस का एलान करेंगे। एफआरपी 9.5 फीसदी के बेसिक रिकवरी रेट से लिंक्ड होता है। रिकवरी रेट गन्ने की पेराई से हासिल शुगर की मात्रा होती है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। साल 2011-12 में यहां का चीनी का रिकॉर्ड (35.76 करोड़ टन) उत्पादन हुआ और इस बंपर प्रोडक्शन की वजह से फिलहाल भारत चीनी का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहा है।

इसके अलावा, सीसीआई ने रिफाइनिंग पामोलिन ऑयल पर टैरिफ वैल्यू में संशोधन को मंजूरी दे दी, ताकि हालिया अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सके। इस कदम से रेडी-टू-ईट पाम ऑयल की कीमत में इजाफा होगा और घरेलू ऑयल रिफाइनरी को कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकेगी।

इंडोनेशिया से पाम ऑयल के सस्ते इंपोर्ट के कारण इस सेगमेंट की घरेलू कंपनियों को जबरदस्त कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, इससे स्थानीय कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ने की संभावना है, क्योंकि कुल वेजिटेबिल ऑयल इंपोर्ट में रिफाइंड पॉम ऑयल की हिस्सेदारी काफी कम है। 2011-12 के ऑयल ईयर (नवंबर-अक्टूबर) में नवंबर-मई के दौरान भारत में रिफाइन्ड पामोलिन का इंपोर्ट बढ़कर 10.9 लाख टन हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह केवल 5.51 लाख टन था।

वर्किंग कैपिटल पर बढ़ सकता है प्रेशर

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ने के मिनिमम प्राइस में 17.25 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस सीजन के लिए यह राशि 145 रुपए प्रति क्विंटल है। इस फैसले से शुगर इंडस्ट्री के वर्किंग कैपिटल पर और प्रेशर बढ़ सकता है